THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) Indigenisation of spare parts for imported equipment is an on-going process to ensure continued spares support. An exercise has been taken up to accelerate the pace of indigenisation by making use of the facilities available in ordnance factories, EME workshops, defence public sector undertakings and units in the civil sector.

देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण इकाइयां

*284. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:
श्री वीरेन जे० शाह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 250 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों में नवयुवकों को किन-किन उद्योगों के लिये प्रशिक्षण देने की योजना है;

(ग) इन प्रशिक्षण इकाइयों पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों में कुल कितने नवयुवकों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने इन इकाइयों के लिये स्थानों के चयन का काम पूरा कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार कितने तथा किन-किन स्थानों पर ऐसी प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना किये जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (च) इस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता देने की एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत लगभग 250 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को आठवीं योजना अवधि के दौरान क्रमिक रूप से सहायता देने का प्रस्ताव है। यह स्कीम ऐसी राज्य-सरकारों, सहकारिताओं, वायत्तशासी निकायों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जायेंगी जो ऐसे केन्द्रों की स्थापना और उन्हें चलाने के इच्छुक हैं। ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में लगभग 50-60 युवकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र को कुछ क्वालिटी परीक्षण उपस्करों सहित संयंत्र और मशीनरी पर होने वाले अनावर्ती व्यय के लिये 2 लाख रुपये की अनुदान सहायता और 1 लाख रुपये आवर्ती निधि के रूप में सहायता स्वरूप देने का प्रस्ताव है। चूंकि अलग-अलग प्रस्ताव राज्य सरकारों के माध्यम से भेजे जाने हैं अतः स्थानवार/राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रस्ताव उचित प्रौद्योगिकी के साथ छोटे खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के संचालन और प्रबन्ध में ग्रामीण लोगों को व्यावहारिक अनुभव के साथ प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है। यह केन्द्र फल और सब्जी, मांस, अनाज, दाल, दूध, पाल्ट्री आदि जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिये मुख्य रूप से प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 में इस स्कीम के लिये 1.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

Contribution made for setting up of ESI Hospitals

*285. SHRI GUNDAPPA KORWAR:
SHRI K.R. JAYADEVAPPA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the contribution made by the Central Government/Employees State Insurance Corporation during the Seventh Five Year Plan period for setting up of ESI hospitals and also the contribution made by State Government's State-wise; and

(b) what is the number of ESI Hospitals which have been started during the Seventh Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) The ESI Corporation does not prepare any five-year plan for construction of ESI hospitals. The ESI hospitals are constructed on "need basis" in accordance with the norms prescribed by the ESI Corporation. The entire cost of construction is met exclusively by the ESI